समक्ष निर्मल *यादव* , माननीय न्यायमूर्ति।

महंत चंद नाथ योगी , – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और *अन्य,* - प्रतिवादियों

क्रिमिनल मिसलेनियस 2005 का 19319 / एम

22 फरवरी 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा *482-* भारतीय *साक्ष्य अधिनियम, 1872* – धारा *25 और 27* -अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बाबा की हत्या–अंधी हत्या–एफआईआर में हमलावर के नाम का जिक्र नहीं–जांच के दौरान याचिकाकर्ता की संलिप्तता का आरोप लगाया गया–याचिकाकर्ता के पास हत्या की साजिश रचने का कोई मकसद नहीं है–अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई हत्या के पीछे का मकसद विश्वसनीय नहीं है–हत्या में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के संबंध में इकबालिया बयान पुलिस के समक्ष दुर्दांत अपराधियों द्वारा दिए गए थे– कोई वसूली नहीं हुई– इस तरह के प्रकटीकरण बयानों को याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस कानूनी सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है– अभियोजन कोई भी मकसद साबित करने में विफल रहा जो याचिकाकर्ता को हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित कर सकता था– अभियुक्त के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ–प्रकृति और दायरा, बताया गया – ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना संभव है कि किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और विवादित कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य सुरक्षित हो जाएगा। – याचिकाकर्ता का मामला एक

ऐसी श्रेणी का गठन करता है जहां उच्च न्यायालय को कानून की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा *482* के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।– याचिका स्वीकार कर ली गई, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की गई कार्यवाही रद्द कर दी गई।

अभिनिर्णित, आमतौर पर, किसी आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को संहिता के प्रावधानों के तहत चलाया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय अंतरिम चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। हालाँकि, मामलों की कुछ श्रेणियां हैं जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना संभव हो कि किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और विवादित कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप, भले ही अंकित मूल्य पर लिए गए हों और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह तय करने के लिए शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखना पर्याप्त होगा कि यह कथित अपराध का खुलासा करता है या नहीं। ऐसे मामलों की एक और श्रेणी हो सकती है जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अपराध का गठन करते हैं लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत नहीं है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहते हैं या सबूत स्पष्ट रूप से असंगत हैं आरोप लगाया गया. ऐसे मामले

हो सकते हैं जहां इसकी सराहना पर कानूनी सबूत प्रश्न में आरोप का समर्थन कर भी सकते हैं और नहीं भी।

(पैरा *12*)

आगे माना गया कि धारा 482 सीआर के तहत उच्च न्यायालय के पास जो शक्तियाँ हैं। पी.सी. बहुत व्यापक प्रकृति और प्रचुरता वाले हैं। हालाँकि, व्यायाम में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। न्यायालय को यह देखने में सावधानी बरतनी होगी कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और इसका प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाता है। न्यायालय को ऐसे मामले में शक्ति का उपयोग करने से बचना चाहिए जहां सभी तथ्य अधूरे और धुंधले हों, खासकर जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हों और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हों और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे तथ्यात्मक हों या कानूनी, बड़े पैमाने पर हों और उन्हें देखा न जा सके। पर्याप्त सामग्री के बिना उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में। बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। शिकायत/एफआईआर को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

(पैरा *13*)

आगे कहा गया कि माना कि घटना स्थल के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और यह अंधे कत्ल का मामला है। एफआईआर में किसी ने बाबा आजाद नाथ की हत्या करने वाले हमलावर का नाम नहीं लिया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि बाबा आजाद नाथ की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने की है। जांच के दौरान याचिकाकर्ता की संलिप्तता सामने आई है।

(पैरा *15*)

आगे कहा गया कि साजिश को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अपराध करने के लिए दिमागों के मिलने को साबित करना होगा। प्रत्येक षडयंत्रकारी को प्रत्येक षडयंत्रकारी कृत्य को अंजाम देने में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, साजिश को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। यद्यपि साजिश हमेशा गोपनीयता में रची जाती है, अभियोजन पक्ष को समझौते की कुछ भौतिक अभिव्यक्ति साबित करनी होगी, हालांकि दो व्यक्तियों की वास्तविक मुलाकात या उन शब्दों को साबित करना आवश्यक नहीं है जिनके द्वारा दो व्यक्तियों ने संवाद किया था। मौजूदा मामले में एकमात्र सबूत, पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से प्रभावित हैं। चूँकि दो प्रकटीकरण बयानों के बाद कोई वसूली नहीं की गई, इसलिए, बयानों का कोई भी हिस्सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत भी साबित नहीं किया जा सका।

(पैरा 2*1*)

इसके अलावा, यह माना गया कि साजिश के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच गैरकानूनी कार्य करने, या गैरकानूनी तरीकों से वैध कार्य करने के लिए समझौते को साबित करना होगा। कानून को किसी विशेष चीज़ को विशेष रूप से डिजाइन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले प्रत्येक साजिशकर्ता के खिलाफ विशिष्ट सबूत की आवश्यकता होती है। षडयंत्र का उद्देश्य यथा निर्धारित सिद्ध होना चाहिए। यह सकारात्मक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन में कोई सकारात्मक सहमति थी या कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए मन मिला था। जब तक प्रत्येक आरोपी के खिलाफ एक विस्तृत विशिष्ट सबूत स्थापित नहीं किया जाता है, जिसने किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक विशेष डिजाइन में भाग लिया था, आईपीसी की धारा 120-बी के तहत कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा *22*)

इसके अलावा, यह माना गया कि जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा है जो याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित कर सकता था। अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाया गया कथित मकसद पूरी तरह से कमज़ोर है। यह अनुमान लगाना बहुत ज्यादा होगा कि आरोपियों ने बाबा आज़ाद नाथ की हत्या करने का फैसला किया होगा, खासकर तब जब पिछले *15* वर्षों से उनके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। चूंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित

है, इसलिए मकसद प्रासंगिकता और महत्व रखता है। अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की अंधे हत्या से जोड़ने के लिए कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत दिखाने में बुरी तरह विफल रहा है और यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा की गई परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूरी नहीं है। सह-अभियुक्त, जो कट्टर अपराधी हैं, ने पुलिस हिरासत में रहते हुए खुलासे वाले बयान दिए हैं और उनके बयानों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे साक्ष्य को पुख्ता कानूनी साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

(पैरा *23*)

आगे माना गया कि यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ एक ऐसी श्रेणी का गठन करती हैं जहाँ इस न्यायालय को कानून की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग को रोकने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

(पैरा *25*)

जे.एस. बेदी, याचिकाकर्ता के वकील।

नरेंद्र सूरा, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

निर्णय

निर्मल यादव, माननीय न्यायमूर्ति।

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 302/120-बी, पी.एस. के तहत 24 जनवरी, 1999 की एफआईआर संख्या 17 को रद्द करने की मांग करता है। बावल, जिला रेवाडी।

2. याचिका में दिए गए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री श्रेयो नाथ गद्दी मठ, अस्थल बोहर के महंत और गुरु थे। याचिकाकर्ता और एक बाबा आज़ाद नाथ महंत श्री श्रेयो नाथ के चेला थे। महंत श्री श्रेयो नाथ ने *24* मई, *1984* को याचिकाकर्ता के पक्ष में उन्हें अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की। *30* जुलाई, *1984* को जिला न्यायालय, करनाल में दायर एक सिविल मुकदमे में, महंत श्री श्रेयो नाथ ने बयान अनुबंध ए-*6* के अनुसार गवाही दी कि उन्होंने सभी समारोहों का पालन करके याचिकाकर्ता को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। महंत श्री श्रेयो नाथ का निधन *7* जनवरी, *1985* को हो गया और याचिकाकर्ता को *9* जनवरी, *1985* को चादर रस्म करके महंत श्री श्रेयो नाथ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बाबा आजाद नाथ ने कभी भी याचिकाकर्ता के महंत पद को चुनौती नहीं दी। उन्होंने महंत श्री श्रेयो नाथ द्वारा निष्पादित वसीयत को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी। बाबा आज़ाद नाथ *1984* से आसलवास गाँव में रहने लगे, जो अस्थल बोहर (रोहतक) में बाबा मस्त नाथ के मठ से लगभग *100* किलोमीटर की दूरी पर है। वे मठ के मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करते थे।

3. आगे यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर *2* श्री ओम प्रकाश चौटाला का क्रोध झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने रुपये की राशि का भुगतान करने की उनकी मांग को पूरा करने से इनकार कर

दिया था। *10* मार्च, *2001* तक उन्होंने *2* करोड़ रुपये जुटा लिए और इसके लिए उन्हें धमकी भरे फोन भी आए। प्रतिवादी नंबर *2* ने अधिकारियों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों के कामकाज में सभी प्रकार की बाधाएं पैदा करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी नंबर *2* के आदेश पर याचिकाकर्ता को जान से मारने की कई धमकियां मिलीं। याचिकाकर्ता ने *5* फरवरी, *2001* को पुलिस अधीक्षक, रोहतक को एक शिकायत सौंपी, जिसके बाद एफआईआर नंबर *42* दिनांक *5* फरवरी, *2001* को आईपीसी की धारा *387* के तहत दर्ज किया गया। पुलिस थाना सदर रोहतक। हालाँकि, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतक को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, रोहतक को याचिकाकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। उपरोक्त आदेश के बावजूद, राज्य सरकार याचिकाकर्ता को कोई सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही। प्रतिवादी संख्या *2* के निर्देशों के तहत, वर्ष *2001* में सुने गए अपराधियों, अर्थात् कृष्ण सिंह, मंजीत सिंह और अशोक कुमार के प्रकटीकरण बयान दर्ज करवाकर, याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा *120*-बी की सहायता से झूठा फंसाया गया था। उपरोक्त एफआईआर संख्या *17* दिनांक *24* जनवरी, *1999* किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाबा आजाद नाथ की हत्या से संबंधित है, जो बाबा आजाद नाथ के पैतृक गांव के निवासी रणधीर सिंह के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी। रणधीर सिंह के मुताबिक *24* जनवरी *1999* को शाम करीब *5* बजे. वह गांव आसलवास स्थित शिव मंदिर में बाबा आजाद नाथ के दर्शन करने गया था। शाम लगभग *6.30* बजे, बाबा आज़ाद नाथ बाहर आए और अमी लाई के तेज पाल, प्रभात के पुत्र जैना और राम पाल के पुत्र ओमबीर सहित सेवकों के साथ बैठे थे। उसी समय एक *25/26* साल का व्यक्ति, जो शर्ट-पैंट पहने हुए था और पीठ पर मुंह छिपाए हुए था, लोई वहां आया और उसने सुल्फा पीने की इच्छा की, जिस पर बाबा ने कहा कि वह उसे सुल्फा नहीं दे सकता, परंतु वह भोजन

कर सकता है। जब उसने भोजन करने से इंकार कर दिया तो बाबा ने उससे कहा, यदि वह भोजन नहीं करना चाहता तो सामने वाले द्वार से जा सकता है। इसके बाद शिकायतकर्ता और अन्य लोग खाना खाने लगे और बाबा पेशाब करने के लिए पीछे की तरफ चला गया। इसके लगभग *4-5* मिनट बाद, फटाका (आतिशबाजी) का एक बड़ा शोर हुआ और बाबा ने भजियो' (भागो) कहा। शोर सुनकर, शिकायतकर्ता और अन्य लोग अपना खाना छोड़कर वार्ड के पीछे की ओर गए और देखा कि बाबा पेड़ के पास अपना मुंह नीचे की ओर लेटे हुए थे और छाती के दाईं ओर से खून बह रहा था। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को संदेह था कि उक्त आगंतुक ने खुद को अंधेरे में छिपाकर बाबा पर गोली चलाई थी, जिसकी आग्नेयास्त्र शॉर्ट्स के कारण मृत्यु हो गई। आगे कहा गया है कि अगर उक्त व्यक्ति उनके सामने आएगा तो उसकी पहचान की जा सकेगी. प्रारंभ में, एफआईआर धारा *302* आईपीसी के तहत दर्ज की गई थी और बाद में धारा *120*-बी आईपीसी जोड़ी गई थी।

4. यह दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता से इंस्पेक्टर, सीआईडी/अपराध, फरीदाबाद सहित पुलिस अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई थी। सीआरपीसी की धारा *161* के तहत याचिकाकर्ता का बयान। पी.सी. *24* जून, *1999* को पुलिस द्वारा भी दर्ज किया गया था और गहन जांच के बाद याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया गया। आरोपी कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद, दबाव, प्रलोभन और धमकी के तहत उससे प्रकटीकरण बयान प्राप्त किया गया था, जो झूठा पाया गया और उसे *3* नवंबर, *1999* को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी द्वारा आरोपमुक्त कर दिया गया। जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के झूठे निहितार्थ को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(i) जांच एजेंसी ने प्रतिवादी संख्या *2* के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और *10* मई *1999* को विभिन्न आपराधिक मामलों में आजीवन कारावास की सजा पाए एक कठोर अपराधी कृष्ण का बयान उसके प्रोडक्शन वारंट पर सुरक्षित कर लिया। उक्त कृष्ण ने याचिकाकर्ता से जुड़े सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल राज सिंह का नाम लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल राज सिंह को किसी बाबा की हत्या की व्यवस्था करने के लिए भेजा था।

(ii) एक अन्य दुर्दांत अपराधी मंजीत सिंह, जो विभिन्न मामलों में शामिल था, का बयान *11* मार्च *2000* को दर्ज किया गया था।

(iii) अशोक कुमार का बयान, जो *11* मार्च *2001* को दर्ज किया गया था।

(iv) जांच एजेंसी ने 27 अप्रैल, 2001 को जय प्रकाश दहिया का बयान दर्ज किया, जिन्होंने 17 मार्च, 2001 को एक हलफनामा दिया था कि उन्होंने छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को बड़े मूल्यवर्ग से बदलवाया था, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था। बाबा आज़ाद नाथ की हत्या करने के लिए कथित भाड़े का हत्यारा।

5. उपरोक्त बयानों के आधार पर, याचिकाकर्ता को वर्तमान एफआईआर में धारा *120*-बी आईपीसी की सहायता से आरोपी बनाया गया है। आगे कहा गया है कि मामले की जांच दो सीआईए इंस्पेक्टरों, कन्हैया लाई और बंसी लाई द्वारा की गई थी, जिन्होंने याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की हत्या के संबंध में निर्दोष पाया था। लेकिन, याचिकाकर्ता को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मामले की दोबारा जांच की गई और याचिकाकर्ता को इसमें शामिल किया गया, हालांकि आरोप के समर्थन में कोई कानूनी सबूत नहीं है। उपर्युक्त गवाह मंजीत सिंह और अशोक कुमार द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने *10* मार्च,

2001 को अपनी गिरफ्तारी तक अपराध में याचिकाकर्ता की कथित संलिप्तता का खुलासा क्यों नहीं किया।

6. आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा *438* के तहत अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की। पी.सी. *14* मार्च, *2001* को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रेवाडी के समक्ष उन्हें छह सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दी गई, जिसकी पुष्टि बाद में *5* जून, *2001* के आदेश द्वारा की गई। राज्य ने आपराधिक विविध मामला दायर किया। याचिकाकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए *18* जुलाई *2001* को संख्या *27699*-एम *2001*। याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने *23* जुलाई, *2001, 21* अगस्त, *2001* और *15* सितंबर, *2001* को प्रभारी, सीआईए स्टाफ, सोनीपत, पुलिस अधीक्षक, सोनीपत, एसएचओ, पुलिस स्टेशन बावल को पत्र भेजकर जांच में शामिल होने की पेशकश की। याचिकाकर्ता *19* सितंबर, *2001* के नोटिस के जवाब में जांच में शामिल होने गया, लेकिन कुछ नहीं किया गया और उसे किसी अन्य अवसर पर बुलाए जाने के लिए वापस भेज दिया गया। किसी बुरे इरादे का संदेह करते हुए, याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी की अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य को नोटिस जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा सीआईए स्टाफ, पुलिस स्टेशन सोनीपत में जांच में शामिल होने के लिए *27* अक्टूबर, *2001* की तारीख तय की गई। . याचिकाकर्ता जांच के लिए उपस्थित हुआ और उससे *27* अक्टूबर, *2001* और फिर *28* अक्टूबर, *2001* को पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर ली। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। इसलिए, याचिकाकर्ता ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और

याचिकाकर्ता को जमानत देने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया।

7. याचिकाकर्ता ने इस आधार पर एफआईआर और उस पर की गई आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है, जो याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की हत्या के लिए रची गई किसी साजिश से दूर से भी जोड़ सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित कहानी हत्या करने के किसी मकसद का संकेत नहीं देती है क्योंकि याचिकाकर्ता को उनके जीवनकाल के दौरान *30* मई, *1984* को महंत श्री श्रेयो नाथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, मृतक बाबा आज़ाद नाथ ने *1984* से *1999* तक *15* साल की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की महंतशिप को कभी चुनौती नहीं दी थी। कहानी यह है कि याचिकाकर्ता ने छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को बड़े मूल्यवर्ग के नोटों से बदलवा लिया था। बैंक के रिकार्ड को देखते हुए *500* का भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। जांच एजेंसी ने मुख्य रूप से कृष्ण, मंजीत सिंह और अशोक कुमार के खुलासे वाले बयानों पर भरोसा किया है, जो पुलिस हिरासत में दर्ज किए जा रहे हैं, कानून में अस्वीकार्य हैं। मंजीत और कृष्ण की पृष्ठभूमि दुर्दांत अपराधियों की थी।

8. राज्य की ओर से, डॉ. चक्किराला संबाशिव राव, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, रेवाडी द्वारा दायर जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है ताकि इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सके। याचिका में दिए गए अधिकांश कथनों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है। हालांकि, बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है। याचिकाकर्ता का नाम *1999* की एफआईआर संख्या *17* की जांच के दौरान सामने आया, जिसमें याचिकाकर्ता की अपराध में संलिप्तता

के संबंध में संदेह था। सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित आदेश, जिसमें पुलिस अधीक्षक, रोहतक को याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था, विवादित नहीं है। यह कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर *2* के आदेश पर स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण याचिकाकर्ता को झूठा फंसाना चाहता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, बावल को आरोपी कृष्ण पुत्र रणधीर सिंह, निवासी गाँव मेहंदीपुर की संदिग्ध संलिप्तता के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर उसका प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया गया और उसे *10* तारीख को जांच में शामिल किया गया। मई, *1999.* पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसके पूर्व सहयोगी राज सिंह ने उससे संपर्क किया था, जिसने उसे बताया था कि बाबा आजाद नाथ की हत्या की जानी है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि याचिकाकर्ता राज सिंह के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहतक की अदालत में सुनवाई की तारीख पर उनसे मिले थे और उन्होंने रुपये की मांग की थी। बाबा आजाद नाथ की हत्या के लिए *10* लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। *12* लाख, लेकिन उक्त रकम बाबा आजाद नाथ की हत्या के बाद दी जानी थी। आगे यह कहा गया है कि जांच के दौरान कृष्ण के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाड़ी की अदालत ने *3* नवंबर, *1999* के आदेश के तहत आरोपमुक्त कर दिया। यह आगे कहा गया है कि बयान दर्ज करने के दौरान धारा *164* सीआर के तहत कृष्ण ने कहा। पी.सी., मंजीत, कांस्टेबल राज सिंह, अशोक और पीतमपुरा निवासी धीरा की संलिप्तता सामने आई।

9. यह कहा गया है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने के लिए कभी भी कोई दुर्भावनापूर्ण प्रयास नहीं किया गया। पुलिस ने देश के कानून का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके से काम किया। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का बयान *24* जून, *1999* को पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उस समय

मामले की जांच इंस्पेक्टर कन्हैया लाई द्वारा की गई थी। हालाँकि, इंस्पेक्टर कन्हैया लाई द्वारा की गई जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई थी। आगे कहा गया है कि मृतक के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों के कारण याचिकाकर्ता घटना के दिन से ही मामले में संभावित संदिग्ध था। यह माना जाता है कि उस समय जांच को कोई खास प्रगति नहीं मिली थी। कृष्ण कुमार द्वारा सीआरपीसी की धारा *164* के तहत बयान दिए जाने के बाद ही भौतिक विकास हुआ था। पी.सी. और उसके बाद आरोपी मंजीत सिंह द्वारा दिया गया खुलासा बयान। इसके बाद, समस्या का कोण बदल दिया गया और जांच पूरी तरह से अलग स्तर पर की गई। ऐसा कहा जाता है कि जय प्रकाश दहिया एक बर्खास्त बैंक क्लर्क था और वह अस्थल बोहर में मंदिर बाबा मस्त नाथ से संबद्ध था क्योंकि केनरा बैंक का एक्सटेंशन काउंटर मठ में स्थित था। उसका याचिकाकर्ता के साथ घनिष्ठ संबंध था और वह किसी भी तरह से उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था। उक्त जय प्रकाश दहिया जांच में शामिल हुए और धारा *161* सीआर के तहत उनका बयान दिया गया। पी.सी. रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने *17* मार्च, *2001* को इस आशय का एक हलफनामा भी दायर किया कि याचिकाकर्ता बाबा आजाद नाथ को खत्म करना चाहता था और रुपये खर्च करने को तैयार था। इसके लिए *20-25* लाख रु. याचिकाकर्ता बाबा आजाद नाथ के खिलाफ पुरानी दुश्मनी पाल रहा था क्योंकि वह महंत श्री श्रेयो नाथ के जीवनकाल के दौरान महंत की सीट के प्रतिस्पर्धी दावेदार थे। आगे कहा गया है कि जय प्रकाश दहिया ने रुपये का आदान-प्रदान किया था। *20* लाख, जिसे याचिकाकर्ता ने रुपये के मुद्रा नोटों में बदलने के लिए राज सिंह को सौंपा था। रुपये से *500* मूल्यवर्ग. *100* मूल्यवर्ग. इस तथ्य का सत्यापन ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रोहतक से करवाया गया। एक विशिष्ट प्रश्न पर, बैंक दस्तावेज़ विद्वान राज्य वकील द्वारा प्राप्त किए गए थे और यह पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेज़ किसी भी तरह से अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं

करते हैं, जैसा कि आगे चर्चा की जाएगी। इसलिए, यह कहा गया है कि याचिका में कोई दम नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि मौजूदा एफआईआर को रद्द किया जाए।

10. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और चला गया हूंमामले के रिकॉर्ड के माध्यम से।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मंजीत और अशोक द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के अनुसरण में याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से कोई वसूली नहीं की गई है। यहां तक कि आज तक कोई पहचान भी नहीं कराई गई है और एफआईआर में उल्लिखित किसी भी आरोपी की गवाहों द्वारा पहचान नहीं कराई गई है, हालांकि एफआईआर में यह उल्लेख किया गया था कि शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्ति हमलावर की पहचान कर सकते हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है, घटना के समय मौजूद कोई भी व्यक्ति जांच में शामिल नहीं हुआ है।

12. मामले से निपटने से पहले, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा *482* के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों की प्रकृति और दायरे पर विचार करना आवश्यक है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संहिता की धारा *482* के प्रावधान उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करते हैं जो संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। न्याय का अंत. उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी निजी मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए या तो कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर, किसी

आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई संहिता के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए और उच्च न्यायालय अंतरिम चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। हालाँकि, कुछ आसान श्रेणियाँ हैं जहाँ कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उच्च न्यायालय के लिए यह विचार करना संभव हो कि किसी आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और विवादित कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य सुरक्षित हो जाएगा। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप भले ही अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, लेकिन कथित अपराध का गठन नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में साक्ष्य की सराहना का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह तय करने के लिए शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखना पर्याप्त होगा कि यह कथित अपराध का खुलासा करता है या नहीं। ऐसे मामलों की एक और श्रेणी हो सकती है जहां आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अपराध का गठन करते हैं लेकिन मामले के समर्थन में या तो कोई कानूनी सबूत नहीं है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहते हैं या सबूत स्पष्ट रूप से असंगत हैं आरोप लगाया गया. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां इसकी सराहना पर कानूनी सबूत प्रश्न में आरोप का समर्थन कर भी सकते हैं और नहीं भी। सर्वोच्च न्यायालय ने एपी राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी और अन्य (*1)* के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में, संहिता की धारा *482* के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के दायरे की जांच करते हुए, निम्नानुसार देखा है*:-*

5. इस प्रकृति के मामले में संहिता की धारा *482* के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित

शक्ति को बचाता है जो संहिता के लागू होने से पहले न्यायालय के पास थी। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, *(i)* संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, *(ii)* अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (*iii)* अन्यथा सुरक्षित करने के लिए। न्याय। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम संभवतः उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है। इसलिए, न्यायालयों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस धारा में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है। सभी अदालतें, चाहे दीवानी हों या फौजदारी, के अभाव में कोई भी स्पष्ट प्रावधान, जैसा कि उनके संविधान में निहित है, ऐसी सभी शक्तियां जो न्याय के प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं, सिद्धांत क्वान्डो लेक्स एलिक्विड अलिक अभिमानी, कॉन्सेडिटूर एट आईडी साइन क्वो रेस इप्सा एसे नॉन पोटेस्ट (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है तो वह उसे वह भी देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता)। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो। इसका प्रयोग पूर्व डेबिटो जस्टिटिया के प्रशासन

के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालतें मौजूद हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास ऐसे दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना या जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जब शिकायत से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों को देखने की अनुमति है, भले ही आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो।

आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (*2*) में सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों की कुछ श्रेणियों का सारांश दिया जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं: -

(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था या निरंतरता के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है, उदाहरण के लिए मंजूरी की चाहत;

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया गया है और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया है, वे कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं;

(iii) जहां आरोप एक अपराध है, लेकिन कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया गया है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहता है।

अंतिम श्रेणी से निपटने में, उस मामले के बीच अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां ऐसे सबूत हैं, जो स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों से असंगत हैं, और ऐसे मामले जहां कानूनी सबूत हैं, प्रशंसा पर, आरोप का समर्थन हो भी सकता है और नहीं भी। आमतौर पर, उच्च न्यायालय इस बात की जांच नहीं करेगा कि विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या इसकी उचित सराहना के बावजूद आरोप टिक नहीं पाएगा। न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सतर्क और विवेकपूर्ण होना चाहिए, लेकिन साथ ही, प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी निजी शिकायतकर्ता के हाथों में किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए प्रतिशोध लेने का एक साधन बन जाए। बेवजह. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाई (*3)* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी का एक नोट जोड़ा था कि ऐसी शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्शाई गई उदाहरणात्मक श्रेणियां इस प्रकार हैं*:-*
*"102. (*एल) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई कंपनी एफआईआर में शामिल है, तो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है, जो कि मजिस्ट्रेट के आदेश

के अलावा संहिता की धारा *156 (1)* के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराता है। संहिता की धारा *155(2)* का दायरा।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा *155 (2)* के तहत माना गया है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संहिता या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण

रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

13. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा *482* सीआर के तहत उच्च न्यायालय के पास जो शक्तियाँ हैं। पी.सी. बहुत व्यापक प्रकृति और प्रचुरता वाले हैं। हालाँकि, व्यायाम में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। न्यायालय को यह देखने में सावधानी बरतनी होगी कि इस शक्ति के प्रयोग में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है और इसका प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाता है। न्यायालय को ऐसे मामले में शक्ति का उपयोग करने से बचना चाहिए जहां सभी तथ्य अधूरे और धुंधले हों, खासकर जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हों और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हों और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे तथ्यात्मक हों या कानूनी, बड़े पैमाने पर हों और उन्हें देखा न जा सके। तत्कालीन में- पर्याप्त सामग्री के बिना सही परिप्रेक्ष्य। बेशक, उन मामलों के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है जिनमें उच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने के अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। शिकायत/एफआईआर को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में **जनता दल आदि बनाम एच.एस. का संदर्भ लिया जा सकता है। चौधरी और अन्य, *(4),* डॉ. रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य और अन्य (*5)*।**

14. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के दायरे की जांच करने के बाद, मैं अब विचार करने के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता हूं - क्या वर्तमान मामले के तथ्य कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को आकर्षित करेंगे*?*

15. वर्तमान मामले में, माना कि घटनास्थल के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और यह अंधे कत्ल का मामला है। एफआईआर में किसी ने बाबा आजाद नाथ की हत्या करने वाले हमलावर का नाम नहीं लिया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि बाबा आजाद नाथ की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने की है। जांच के दौरान याचिकाकर्ता की संलिप्तता सामने आई है। राज्य द्वारा दायर जवाब में, हत्या के पीछे का मकसद याचिकाकर्ता और मृतक के बीच बोहर मठ के महंत की गद्दी को लेकर मौजूदा तनाव था और इसलिए, याचिकाकर्ता बाबा आज़ाद नाथ को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हालाँकि, निर्विवाद तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी द्वारा सुझाया गया मकसद विश्वसनीय नहीं है। याचिकाकर्ता और बाबा आज़ाद नाथ दोनों महंत श्री श्रेयो नाथ के चेला थे। अपने जीवनकाल के दौरान, महंत श्री श्रेयो नाथ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में उन्हें गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी। महंत श्री श्रेयो नाथ ने *30* जुलाई, *1984* को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल की अदालत के समक्ष गवाही दी कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए एक वसीयत निष्पादित की थी और सभी अपेक्षित समारोह किए गए थे। वर्ष *1984* में बाबा आज़ाद नाथ को ट्रस्ट के शासी निकाय से निष्कासित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, बाबा आज़ाद नाथ वर्ष *1984* में ही आसलवास गाँव में स्थानांतरित हो गए। महंत श्री श्रेयो नाथ की मृत्यु *7* जनवरी, *1985* को हुई और याचिकाकर्ता को *9* जनवरी, *1985* को गद्दी का महंत बनाया गया। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बाबा आज़ाद नाथ ने महंत श्री श्रेयो नाथ की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के उत्तराधिकार पर कभी सवाल उठाया था। या उन्होंने कभी भी *24* मई, *1984* की वसीयत की वैधता को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है और न ही इस न्यायालय के समक्ष कुछ भी रखा गया है, जब से बाबा आज़ाद नाथ आसलवास में स्थानांतरित हुए थे या रहे थे। शासी निकाय से निष्कासित, उन्होंने

ट्रस्ट के कामकाज और कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का बाबा आज़ाद नाथ की हत्या की साजिश रचने का कोई मकसद नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाए गए मकसद का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

16. जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किया गया एक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक दुर्दांत अपराधी कृष्ण कुमार के बयान के रूप में है। उक्त बयान पुलिस अभिरक्षा में दर्ज किया गया. राज्य द्वारा दायर जवाब में यह दलील दी गई है कि बाबा आज़ाद नाथ की हत्या में उनकी संलिप्तता के संबंध में एक गुप्त सूचना प्राप्त होने पर कृष्ण कुमार की उपस्थिति के लिए ऑप प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया गया था। हालाँकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त गुप्त जानकारी का स्रोत क्या था। उक्त कृष्ण कुमार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाडी द्वारा *3* नवंबर, *1999* को आरोपमुक्त कर दिया गया था क्योंकि जांच एजेंसी ने कहा था कि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं था। अपनी रिहाई के *17* महीने से अधिक समय के बाद, कृष्ण कुमार ने *24* अप्रैल, *2001* को धारा *164* सीआर के तहत अपना बयान दर्ज कराया। पी.सी. उक्त बयान को पढ़ने से, जो रिकॉर्ड पर रखा गया है, पता चलता है कि वह एक मंजीत सिंह से मिला था जिसने उसे बताया कि उसने रुपये के बदले में बाबा आज़ाद नाथ की हत्या कर दी थी। एक अशोक के माध्यम से *1.50* लाख रुपये का भुगतान किया था। *25,000.* हालाँकि, इस तथ्य का खुलासा उन्होंने पहले नहीं किया था जब उनकी उपस्थिति प्रोडक्शन वारंट पर सुरक्षित थी और धारा *161* सीआर के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। पी.सी. *10* मई, *1999* को दर्ज किया गया था। दो बयानों के बीच इतना लंबा समय-अंतराल उनके बयान की सत्यता को संदिग्ध बनाता है। यह भी बेहद संदिग्ध है कि उम्रकैद की सजा पाने वाला कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सीआरपीसी की धारा *164* के तहत बयान देगा। पी.सी. विशेषकर तब जब उसने

हिरासत में पूछताछ के दौरान उक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया। विवाद का दूसरा पहलू, जो कृष्ण की गवाही पर संदेह पैदा करता है, वह यह है कि जांच एजेंसी ने खुद ही उन्हें बरी करवा दिया था. ऐसा प्रतीत होता है कि उसका उपयोग केवल याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की अंधे हत्या में शामिल करने के लिए किया गया था। उनके बयान के अनुसार, एक कांस्टेबल राज सिंह और याचिकाकर्ता उनसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रोहतक की अदालत में मिले और उन्होंने रुपये की मांग की थी। बाबा आज़ाद नाथ की हत्या के लिए *10* लाख रुपये की राशि की पेशकश की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने बाबा आज़ाद नाथ की हत्या के लिए *10* लाख रुपये की राशि की पेशकश की थी। *12* लाख, जो फिर से काफी असंभव लगता है क्योंकि कोई भी इससे अधिक रुपये की राशि का भुगतान नहीं करेगा। जिस कार्य के लिए *12* लाख रुपये की मांग की गयी. *10* लाख ही बना है. उसके मुताबिक वह बाबा आज़ाद नाथ की हत्या करने के लिए तैयार हो गया था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका. उनके कथन के अनुसार, एक अन्य दुर्दांत अपराधी मंजीत सिंह ने उनसे सोनीपत जेल में मुलाकात की और खुलासा किया कि उन्होंने रुपये की राशि के लिए बाबा आजाद नाथ की हत्या की थी। मात्र *1.5* लाख. मई, *1999* में दर्ज किए गए अपने पहले बयान में कृष्ण द्वारा उनके और मंजीत के बीच हुई बातचीत का खुलासा नहीं करने का तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह केवल याचिकाकर्ता को फंसाने की एक चाल थी।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन अन्य सबूतों पर भरोसा किया गया वह पुलिस के समक्ष मंजीत सिंह और अशोक कुमार के खुलासे वाले बयान हैं। निर्विवाद रूप से, पुलिस के समक्ष दिए गए प्रकटीकरण बयान जिसके अनुसरण में कोई वसूली नहीं हुई है, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए, ऐसे प्रकटीकरण बयानों को याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस कानूनी सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस तरह, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए

प्रकटीकरण बयान, किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्रशंसनीय मामला नहीं बनाते हैं।

18. *11* मार्च, *2000* को दर्ज किए गए मंजीत सिंह के इकबालिया बयान (अनुलग्नक ए-*4)* के अनुसार, अशोक कुमार पुत्र नफे सिंह, निवासी बाकनेर, पी.एस. जनवरी *1999* में नरेला सोनीपत उसके पास आया। उसने उससे (मंजीत) कहा कि वह एक व्यक्ति की हत्या कराना चाहता है। मंजीत सिंह ने रुपये की मांग की. *2* लाख, लेकिन वह रुपये देने को तैयार था। *1.5* लाख. उसने आगे बताया कि अशोक उसे डेरा दिखाने के लिए डेरा बाबा आसलवास ले गया और खुद वहां से चला गया। उन्हें रुपये का भुगतान किया गया था। खर्च के रूप में *1000* रुपये और काम पूरा होने के बाद शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया गया था। उसके मुताबिक उसने अपनी पिस्तौल से बाबा पर गोली चला दी और मौके से भाग गया. इसके बाद उसने अशोक कुमार को सूचित किया जिसने उसे रुपये दिए थे। *1.5* लाख. उसके मुताबिक उसने पिस्तौल को नाला के पास झाड़ियों में फेंक दिया था. नफे सिंह के बेटे अशोक कुमार ने अपने बयान (अनुलग्नक ए-*3)* में कहा है कि रणधीर सिंह उर्फ धीरा नामक व्यक्ति ने उसे एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए कहा था और इस पर उसने मंजीत से संपर्क किया और उसे रुपये की राशि सौंपी। *1.5* लाख. उसने आगे बताया कि रणधीर उसे गांव आसलवास ले गया और बाबा व मंदिर दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद मंजीत ने बाबा आजाद नाथ की हत्या कर दी और दो दिन बाद रणधीर ने उसे रुपये दिए। *2* लाख. उन्होंने आगे कहा कि बाबा आजाद नाथ की हत्या बाबा चांदनाथ के कहने पर रणधीर और राज सिंह ने की थी. हालाँकि, इन दोनों गवाहों में से किसी से भी उनके प्रकटीकरण बयानों के अनुसरण में कोई वसूली नहीं की गई है। कथित हत्यारे मंजीत की आज तक कोई पहचान भी जांच एजेंसी नहीं करवा पाई है, जबकि एफआईआर में साफ लिखा है कि जब हमलावर डेरे में आया था तो तेज पाल, जैना, परभता, ओमबीर और

प्रकाश भी मौजूद थे। लोग हमलावर की पहचान कर सकते हैं. यहां तक कि उपरोक्त व्यक्तियों के बयान भी, जिनके बारे में कहा गया था कि वे उस दिन उपस्थित थे, आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं। सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों से कोई बरामदगी नहीं हुई है, उन्हें वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी सबूत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अभियुक्त पर अपराध की उंगली उठाने के लिए घटनाओं और परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है। भले ही, तर्क के लिए, यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ रिकॉर्ड पर दो इकबालिया बयान हैं, लेकिन किसी भी पुष्ट परिस्थितियों के अभाव में, इन दोनों बयानों में से किसी को भी अकाट्य या हानिकारक सबूत नहीं कहा जा सकता है। किसी भी तरह से, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि याचिकाकर्ता ने बाबा आज़ाद नाथ की हत्या की साजिश रची थी।

19. विद्वान राज्य वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि कांस्टेबल राज सिंह, जो याचिकाकर्ता के साथ सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था, ने आरोपी कृष्ण से मुलाकात की थी, जो जांच एजेंसी के संस्करण का समर्थन करता है। ऐसा तर्क भ्रामक है, क्योंकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं है कि राज सिंह कभी कृष्ण से मिले थे।

20. इसके अलावा, जय प्रकाश दहिया का यह बयान कि याचिकाकर्ता ने उनसे छोटे मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बड़े मूल्यवर्ग में बदलने के लिए कहा था, बैंक के प्रमाण पत्र से भी गलत साबित होता है, जो याचिका के साथ अनुबंध ए-*5* के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक ए-*5* के अनुसार, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि रुपये की कोई राशि है या नहीं। *500* मूल्यवर्ग के नोटों को छोटे मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया गया था क्योंकि शाखा में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। आगे कहा गया है कि उनकी नकद जमा बही के अनुसार, अधिकतम नोट रुपये के हैं। दिसंबर *1998* के

महीने में *500* रुपये के नोट थे। *29* अक्टूबर *1998* को *1619000* जिसमें से रु. *30* दिसंबर, *1998* को *1350000* भारतीय रिज़र्व बैंक, सोनीपत रोड, रोहतक की करेंसी चेस्ट में जमा किए गए थे। इस प्रकार, जय प्रकाश दहिया का यह कथन कि उन्होंने छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को बड़े मूल्यवर्ग के नोटों से बदलवाया था, इस प्रमाण पत्र द्वारा पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है।

21. साजिश को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अपराध करने के लिए दिमागों के मिलने को साबित करना होगा। प्रत्येक षडयंत्रकारी को प्रत्येक षडयंत्रकारी कृत्य को अंजाम देने में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, साजिश को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है। यद्यपि साजिश हमेशा गोपनीयता में रची जाती है, अभियोजन पक्ष को समझौते की कुछ भौतिक अभिव्यक्ति साबित करनी होगी, हालांकि दो व्यक्तियों की वास्तविक मुलाकात या उन शब्दों को साबित करना आवश्यक नहीं है जिनके द्वारा दो व्यक्तियों ने संवाद किया था। मौजूदा मामले में एकमात्र सबूत, पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *25* के प्रावधानों से प्रभावित हैं। चूँकि दो प्रकटीकरण बयानों के बाद कोई वसूली नहीं की गई, इसलिए, बयानों का कोई भी हिस्सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा *27* के तहत भी साबित नहीं किया जा सका।

22. साजिश के आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच गैरकानूनी कार्य करने, या गैरकानूनी तरीकों से वैध कार्य करने के लिए सहमति साबित करनी होगी। कानून को किसी विशेष चीज़ को विशेष रूप से डिजाइन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले प्रत्येक साजिशकर्ता के खिलाफ विशिष्ट सबूत की आवश्यकता होती है। षडयंत्र का उद्देश्य यथा निर्धारित सिद्ध होना चाहिए। यह सकारात्मक साक्ष्य द्वारा

सिद्ध किया जाना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन में कोई सकारात्मक सहमति थी या कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए मन मिला था। जब तक प्रत्येक आरोपी के खिलाफ एक विस्तृत विशिष्ट सबूत स्थापित नहीं किया जाता है, जिसने किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक विशेष डिजाइन में भाग लिया था, आईपीसी की धारा *120*-बी के तहत कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सकता है।

23. वर्तमान मामले में, जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष किसी भी मकसद को साबित करने में विफल रहा है जो याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की हत्या की साजिश रचने के लिए प्रेरित कर सकता था। जैसा कि फैसले के पहले भाग में चर्चा की गई है, कथित मकसद पूरी तरह से कमजोर है। यह अनुमान लगाना बहुत ज्यादा होगा कि आरोपियों ने बाबा आज़ाद नाथ की हत्या करने का फैसला किया होगा, खासकर तब जब पिछले *15* वर्षों से उनके बीच हितों का कोई टकराव नहीं था। चूंकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए मकसद प्रासंगिकता और महत्व रखता है। अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता को बाबा आज़ाद नाथ की अंधे हत्या से जोड़ने के लिए कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत दिखाने में बुरी तरह विफल रहा है और यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा की गई परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला भी पूरी नहीं है। सह-अभियुक्त, जो कट्टर अपराधी हैं, ने पुलिस हिरासत में रहते हुए खुलासे वाले बयान दिए हैं और उनके बयानों से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे साक्ष्य को पुख्ता कानूनी साक्ष्य नहीं माना जा सकता। नोट बदलने के संबंध में जय प्रकाश दहिया का बयान दस्तावेजी साक्ष्य यानी बैंक के प्रमाण पत्र से भी गलत साबित होता है। रुपये का कथित भुगतान। बाबा आजाद नाथ की हत्या के लिए *20* लाख की सुपारी भी साबित नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा *120*-बी के जरिए फंसाने की मांग की गई है। सह-अभियुक्तों में से एक कृष्ण, जिसने कहा कि उसे बाबा आज़ाद नाथ की हत्या करने के लिए कहा गया

था, ने आगे कहा था कि उसका आदमी इस कार्य को पूरा नहीं कर सका। उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य दुर्दांत अपराधी मंजीत ने बाबा आजाद नाथ की हत्या करने के बाद उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा, कृष्ण को अभियोजन पक्ष ने *3* नवंबर, *1999* को ही बरी कर दिया था।

24. याचिकाकर्ता के खिलाफ रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि जिस तरह से जांच की गई, उसमें सब कुछ ठीक नहीं था। साजिश को साबित करने के लिए, आचरण और आसपास की परिस्थितियों को कथित अपराधों के अनुरूप होना चाहिए और बहुत दूर नहीं होना चाहिए। यह साबित करने के लिए कोई कनेक्टिंग या पुष्ट सबूत नहीं है कि कांस्टेबल राज सिंह और रणधीर सिंह अशोक से मिले थे या वे अशोक के बारे में भी जानते थे। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंजीत अशोक को जानता था। अशोक के बयान के अनुसार, उसकी मौसी के बेटे प्रदीप कुमार ने उसे मंजीत से मिलवाया था। यहां तक कि उस लिंक साक्ष्य यानी प्रदीप कुमार से भी गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है। इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण सबूत कथित हमलावर मंजीत की उन लोगों द्वारा पहचान करना हो सकता है जिनके बारे में कहा गया है कि वे बाबा आज़ाद नाथ के डेरे पर उस समय मौजूद थे जब मंजीत कथित तौर पर वहां गया था। लेकिन जांच एजेंसी द्वारा आरोपी मंजीत की कोई पहचान नहीं करायी गयी।

25. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ एक ऐसी श्रेणी का गठन करती हैं जहाँ इस न्यायालय को कानून की प्रक्रिया के स्पष्ट दुरुपयोग को रोकने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

26. नतीजतन, याचिका स्वीकार की जाती है और एफआईआर नंबर 17, दिनांक 24 जनवरी, 1999, धारा 302/120-बी आईपीसी, पुलिस स्टेशन बावल के तहत और उस पर की गई सभी बाद की कार्यवाही केवल वर्तमान याचिकाकर्ता के आधार पर रद्द की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा